Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 27-11-2006

Participants : Mistry Shri Madhusudan Devram

>

Title : Need to provide relief to people affected due to riots in Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh.

श्री मधुसूदन मिस्त्री: सभापति महोदय, गुजरात में वर्ा 2001 में हुए दंगों के दौरान जो लोग मारे गये या जो उनसे प्रभावित हुए, उनके रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के इनएडिक्वेट मैजर्स की ओर मैं इस हाउस का ध्यान आकर्ति करना चाहता हूं। यह बड़े दुख और खेद की बात है कि उस वक्त के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 150 करोड़ रुपये यहां से गुजरात सरकार को रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के लिए दिये थे। उस पैसे में से कितने पैसे गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार को वापस दिये, उसका पूरा ब्यौरा हमारे पास मौजूद है। मैं सरकार का ध्यान आकर्ति करना चाहता हूं कि जो लोग दंगों से प्रभावित हुए, जिनके मकान नट हो गये, जो लोग इंजर्ड हो गये या मारे गये, उन प्रभावित लोगों की कालोनियों या बस्तियों में उन्होंने अपने आप ही जो मकान बनाये हैं, वहां राज्य की तरफ से न कोई लाइट की सुविधा दी गई है, न वहां स्कूल बनाये गये हैं और न ही रास्ते बनाये गये हैं और न ही उनके लिए कोई दूसरी फैसिलिटीज क्रिएट की गई हैं। मैं जॉब और इम्पलायमैन्ट की बात नहीं करता। लेकिन गुजरात में एक ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई है कि जहां डेलिबरेटली राज्य की ओर से इस तरह का वर्तन किया जा रहा है, as if they are unwanted people in the State. राज्य में उन लोगों की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी स्थिति वहां पैदा की जा रही है।

सभापति महोदय : आपकी मांग क्या है?

श्री मधुसूदन मिस्त्री : सर, मुझे बोलने दीजिए। मैं हाउस का ध्यान आकर्ति कर रहा हूं। यह मैं फैक्ट बता रहा हूं, मैं इसे किसी पोलिटिकल एंगल से नहीं देख रहा हूं। I feel they are also citizens of this country and they should be treated like any other citizen of the country. The State is highly biased against them and is not providing any adequate relief and rehabilitation measures.

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि जहां-जहां दंगों के दौरान लोग मारे गये, चाहे वे किसी भी कम्युनिटी के हों, चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान हों, उनके रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के बारे में सहायता राशि को बढ़ाया जाए।

सभापति महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि राज्य अपने आपमें वहां जो डिस्क्रिमिनेशन रखता है, किसी को एक लाख, किसी को दो लाख, किसी को पांच लाख और किसी को दस लाख रुपये देते हैं।

MR. CHAIRMAN : Please take your seat.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : इसके बजाय पूरे नेशनवाइज उसके नॉर्म्स तैयार किये जाएं और केन्द्र सरकार के उन नॉर्म्स के मुताबिक राज्य लोगों को सहूलियतें दें तथा रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करे। यही मेरी मांग है।